



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 10, 2014/माघ 21, 1935

No. 50]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 10, 2014/MAGHA 21, 1935

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 4 फरवरी, 2014

सं. टीएएमपी/13/2009-वीपीटी.— महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49, और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार, विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के दरमान की वैधता को विस्तारित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/13/2009-वीपीटी

विशाखापत्तन न्यास

आवेदक

कोरमः

(i) श्री टी.एस. बालासुब्रह्मण्यम, सदस्य (वित्त)

(ii) श्री चन्द्र भान सिंह, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(जनवरी 2014 के 10वें दिन पारित)

यह मामला विशाखापत्तन पत्तन न्यास (वीपीटी) के मौजूदा दरमान की वैधता के विस्तार से संबंधित है।

2. वीपीटी का मौजूदा दरमान (एसओआर) इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार आदेश सं. टीएएमपी/13/2009-वीपीटी दिनांक 18 फरवरी 2011, जिसे 31 मार्च 2011 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था, द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह आदेश दरमान की वैधता 31 मार्च 2013 तक निर्धारित करता है। यह प्राधिकरण वीपीटी के दरमान की वैधता दो बार विस्तारित कर चुका है। इस प्राधिकरण ने पिछली बार वीपीटी के मौजूदा दरमान की वैधता अपने आदेश दिनांक 29 अक्टूबर 2013 द्वारा 31 दिसम्बर 2013 तक विस्तारित की थी।

3.1 वीपीटी द्वारा अपने पत्रों दिनांक 8 फरवरी 2013 और 22 मार्च 2013 द्वारा दाखित किया गया प्रस्ताव संबद्ध उपयोक्ताओं/उपयोक्ता एसोसिएशन के साथ विचार-विमर्श के लिए लिया गया है। हमारे पत्र दिनांक 8 अगस्त 2013 द्वारा वीपीटी से मांगी गई अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण 19 नवम्बर 2013 को भेजा गया है। इस प्रस्ताव पर संयुक्त सुनवाई 20 सितम्बर 2013 को आयोजित की गई थी।

3.2 तत्पश्चात्, वीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 18 दिसम्बर 2013 द्वारा उल्लेख किया था कि मैं एस्सार के साथ रियायत अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के अद्यतन विकास के मद्देनजर, उसके प्रस्ताव में यात्यात, आय अनुमानों और घाटा अनुमानों में बदलाव किया जा सकता है। इसके सामान्य संशोधन प्रस्ताव पर प्रभाव रखते हुए वीपीटी द्वारा बताई गई उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर, वीपीटी को मैं एस्सार के साथ रियायत अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने के मद्देनजर अपने प्रस्ताव को अद्यतन करने और अपना अद्यतन किया गया प्रस्ताव 7 जनवरी 2014 तक प्रस्तुत करने के लिए हमारे पत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2013 द्वारा सलाह दी गई है।

4. वीपीटी को अभी अद्यतन किया गया प्रस्ताव दाखित करना है। जब पत्तन से अद्यतन किया गया प्रस्ताव प्राप्त होगा तो उसकी जांच की जाएगी। इसलिए, इस प्राधिकरण द्वारा मामले पर अंतिम निर्णय लेने में कुछ और समय लगेगा।

5. इसी बीच, पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) में सरकार ने प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2005 की वैधता 31 मार्च 2014 तक अथवा अगले आदेश तक विस्तारित की है। एमओएस द्वारा दी गई सलाह अनुसार, इस प्राधिकरण ने अपने आदेश सं. टीएएमपी/21/2009-डब्ल्यूएस दिनांक 20 दिसम्बर 2013, जिसे जी.सं. 340 द्वारा 26 दिसम्बर 2013 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है, द्वारा प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2005 की वैधता को विस्तारित किया है।

6. मौजूदा दरमान की वैधता 31 दिसम्बर 2013 को समाप्त हो चुकी है। वीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 18 दिसम्बर 2013 द्वारा अपने दरमान की वैधता को विस्तारित करने का अनुरोध भी किया है। यह विचार करते हुए कि वीपीटी को अभी अपना अद्यतन किया गया प्रस्ताव दाखिल करना है और यह स्वीकार करते हुए कि जब अद्यतन किया गया प्रस्ताव प्राप्त होगा तब उसकी जांच करने और अंतिम रूप से विचार किए जाने में समय लगेगा यह भी स्वीकार करते हुए कि प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2005 की वैधता 31 मार्च 2014 तक विस्तारित की गई है, यह प्राधिकरण वीपीटी के मौजूदा दरमान की वैधता 31 मार्च 2014 तक अथवा संशोधित दरमान के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तारित करता है।

7. यदि स्वीकार्य लागत और स्वीकार्य प्रतिलाभ से अधिक कोई अतिरिक्त अधिशेष 1 अप्रैल 2013 के बाद की अवधि के लिए प्रकट होता है तो इसके कार्यनिष्पादन की समीक्षा के दौरान, ऐसा अतिरिक्त अधिशेष निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णतः समायोजित किया जाएगा।

टी. एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञा. III /4/असा./143/13]

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

### NOTIFICATION

Mumbai, the 4th February, 2014

**No. TAMP/13/2009-VPT.**—In exercise of the powers conferred under Sections 48, 49, and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the Scale of Rates at the Visakhapatnam Port Trust as in the Order appended hereto.

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/13/2009-VPT

The Visakhapatnam Port Trust

— - -

Applicant

### QUORUM

(i) Shri T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii) Shri Chandra Bhan Singh, Member (Economic)

### ORDER

(Passed on this 10th day of January 2014)

This relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Visakhapatnam Port Trust (VPT)

2. The existing Scale of Rates (SOR) of the VPT was last approved by this Authority vide Order No. TAMP/13/2009-VPT dated 18 February 2011 which was notified in the Gazette of India on 31 March 2011. The Order prescribes the validity of the SOR till 31 March 2013. This Authority has extended the validity of SOR of VPT twice. This Authority has last extended the validity of the existing SOR of VPT till 31 December 2013 vide its Order dated 29 October 2013.

3.1 The proposal filed by the VPT vide its letter dated 8 February 2013 and 22 March 2013 is taken on consultation with the concerned users/user association. The additional information/clarification sought from the VPT vide our letter dated 8 August 2013 furnished on 19 November 2013. Joint hearing on the proposal was held on 20 September 2013.

3.2 Subsequently, VPT vide its letter dated 18 December 2013 has pointed out that in view of latest development of signing of Concession Agreement with M/s. Essar, the traffic, income estimates and deficit estimates, in its proposal may undergo a change. In view of the above position brought out by the VPT having an impact on its general revision proposal, the VPT has been advised vide our letter dated 31 December 2013 to update its proposal in view of signing the Concession Agreement with M/s. Essar and submit its updated proposal by 7 January 2014.

4. The VPT is yet to file its updated proposal. The updated proposal when received from the port will have to be examined. Hence, it will take some more time for the case to mature for consideration of this Authority.

5. In the meantime, the Government in Ministry of Shipping (MOS) has extended the validity of Tariff Guidelines, 2005 till 31 March 2014 or until further orders. As advised by the MOS, this Authority has extended the validity of Tariff Guideline, 2005 vide its Order No. TAMP/21/2009-WS dated 20 December 2013 which is notified in the Gazette of India on 26 December 2013 vide G. No. 340.

6. The validity of the existing SOR expired on 31 December 2013. The VPT vide its letter dated 18 December 2013 has also requested to extend the validity of its SOR. Considering that the VPT is yet to file its updated proposal and recognising the time required for examining the updated proposal when received and for the case to mature for final consideration and also recognizing that the validity of the Tariff Guidelines, 2005 is extended till 31 March 2014, this Authority extends the validity of the existing SOR of the VPT from the date of its expiry till 31 March 2014 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates, whichever is earlier.

7. If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 1 April 2013, during the review of its performance, such additional surplus will be set off fully in the tariff to be determined.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT. III/4/Exty./143/13]